Advanced International Journal for Research (AIJFR)
E-ISSN: 3048-7641 ● Website: www.aijfr.com ● Email: editor@aijfr.com

वंचित समुदायों के सतत विकास में मध्यप्रदेश पर्यटन की भूमिका

निर्मला त्रिपाठी,[1] डॉ॰ राकेश कुमार,[2]

[1]शोधार्थी, सामाजिक विज्ञान संकाय, आरकेडीएफ विश्वविद्यालय, भोपाल
[2]सह - प्राध्यापक, सामाजिक विज्ञान संकाय, आरकेडीएफ विश्वविद्यालय, भोपाल

सारांश

यह शोध पत्र मध्य प्रदेश राज्य के वंचित और आदिवासी समुदायों के सतत विकास में पर्यटन क्षेत्र की बहुआयामी भूमिका का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। पर्यटन न केवल प्रदेश की आर्थिक वृद्धि का प्रमुख स्रोत है, अपितु आदिवासी व अन्य वंचित समूहों के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण माध्यम साबित हुआ है। पर्यटन गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय समुदायों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में स्थाई सुधार हुआ है, इसके अतिरिक्त, पर्यटन के अंतर्गत संचालित प्रशिक्षण तथा कौशल विकास कार्यक्रमों ने इन समुदायों के सामाजिक सशक्तिकरण में उल्लेखनीय योगदान दिया है।सांस्कृतिक संरक्षण के दृष्टिकोण से, पर्यटन ने आदिवासी परंपराओं, जीवन शैली एवं हस्तशिल्प को जीवित रखने और वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह पर्यटन आधारित गतिविधियां, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन की दिशा में भी प्रोत्साहन प्रदान करती हैं, जो सतत विकास के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। यह शोध मध्य प्रदेश में पर्यटन से जुड़े विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी पहलों, नीतिगत संरचनाओं, और स्थानीय हितधारकों की भागीदारी का समेकित मूल्यांकन करता है। साथ ही, पर्यटन के माध्यम से वंचित वर्ग के सतत सामुदायिक विकास की दिशा में अभूतपूर्व प्रगति के साथ-साथ उनसे जुड़ी चुनौतियों जैसे अवसंरचनात्मक सीमाएं, पर्यावरणीय दबाव एवं सामाजिक असमानताओं का भी वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करता है।अतः यह शोध पर्यटन को सामाजिक-आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण उपकरण मानता है, जो मध्य प्रदेश के वंचित समुदायों के कौशल सशक्तिकरण, रोजगार सृजन, सांस्कृतिक संरक्षण और जीवन स्तर में सुधार के कारण सतत विकास की राह को सरल एवं संभव बनाता है। इस शोध पत्र में स्थानीय सरकारी नीतियों एवं विकास योजनाओं की भूमिका को भी प्रमुखता से रेखांकित किया गया है, जो क्षेत्रीय विकास को और सशक्त बनाने हेतु आवश्यक हैं।

1. प्रस्तावना

मध्य प्रदेश राज्य, जो भारत के भौगोलिक केंद्र में स्थित है, प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत और जनजातीय विविधता के दृष्टिकोण से अत्यंत समृद्ध राज्य है। यह क्षेत्र विभिन्न जनजातीय समुदायों का निवास स्थान है, जिनकी सांस्कृतिक परंपराएं, जीवनशैली एवं सामाजिक आर्थिक व्यवहार राज्य की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग है। आदिवासी तथा वंचित समुदायों के संदर्भ में पर्यटन ने न केवल एक आर्थिक संसाधन के रूप में, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तनकारी उपकरण के रूप में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से इन समुदायों को न केवल आय और रोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए हैं, बल्कि यह उनके कौशल विकास के लिए भी एक महत्वपूर्ण कारक बनकर साबित हुआ है। स्थानीय स्तर पर भी पर्यटन से उत्पन्न रोजगार, जैसे कि हस्तशिल्प निर्माण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक भोजन सेवा और गाइडिंग आदि, इन समूहों को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसरित कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, पर्यटन ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में आर्थिक विकास का साधन बन रहा है सतत, जो किसानों की पारंपरिक कृषि आधारित आय में नए अवसर जोड़कर उसे विविधता प्रदान करता है। सामाजिक स्तर पर भी पर्यटन ने वंचित समुदायों में जागरूकता, पहचान और संस्कृति के संरक्षण को प्रोत्साहित किया है , जिससे उनकी सामाज में स्थिति में उतरोतर वृद्धि हुई है, इसके साथ ही, सतत विकास के दृष्टिकोण से, पर्यटन स्थानीय वन्यजीवों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है, क्योंकि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यावरण संरक्षण अपरिहार्य होता जा रहा है, यह अध्ययन मध्य प्रदेश सरकार एवं अन्य हितधारकों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं पर्यटन विकास के पहलों की प्रभावशीलता को विश्लेषित करता है। अतः यह अध्ययन स्थानीय वंचित एवं आदिवासी समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकीय विकास में पर्यटन के अन्तरसंबंधित प्रभावों का समग्र, वैज्ञानिक एवं नीति-समर्थित विश्लेषण प्रस्तुत करता है, यह प्रदेश के सतत एवं समावेशी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में कार्य करता है।

2. साहित्य समीक्षा

मध्य प्रदेश राज्य में पर्यटन के माध्यम से वंचित एवं जनजातीय समुदायों के सतत सशक्तिकरण संबंधी शोध व नीतिगत दस्तावेज़ सामुदायिक सहभागिता को सुदृढ़ीकरण का आधार मानते हैं। राज्य की नवीनतम पर्यटन नीति 2025 के अंतर्गत स्थानीय समुदायों की पर्यटन गतिविधियों में भागीदारी, आजीविका एवं कौशल विकास का प्रभावी तंत्र स्थापित किया गया है। नीति में सांस्कृतिक संरक्षण, स्थानीय जीवनशैली व परंपराओं के संवर्धन के साथ-साथ ग्रामीण पर्यटन, होम-स्टे, और पारंपरिक शिल्पगृह योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है, जिससे न केवल संस्कृति के संरक्षण को बल मिला है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार सृजन के नए अवसर सृजित हुए हैं।

सामुदायिक-आधारित पर्यटन (Community-based tourism) मॉडलों से संबंधित शोध यह प्रमाणित करते हैं कि इससे वंचित समुदायों में समावेशिता, सामाजिक न्याय, आत्मनिर्भरता और पर्यटन संसाधनों पर स्थानीय स्वामित्व का विस्तार हुआ है। जिससे न केवल उनकी आय में, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलता है। इसी श्रृंखला में, गोंड जनजातियों पर केंद्रित केस स्टडीज़ इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि, पारंपरिक कला, संगीत-नृत्य एवं सांस्कृतिक अनुभवों की वैश्विक पहचान बढ़ने से सामाजिक सशक्तिकरण व आत्मविश्वास का संचार हुआ है।

महिला सशक्तिकरण की बात करें तो हाल के वर्षों में 'महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल परियोजना' आदि सरकारी पहलों ने स्वरोज़गार, उद्यमिता व नेतृत्व क्षमता विकसित करने में महिलाओं की भूमिका को सुपुष्ट किया है। इन पहलों के कारण पर्यटन क्षेत्र में महिला सहभागिता, कौशल प्रशिक्षण एवं सामुदायिक नेतृत्व को बढ़ावा मिला है।

ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के अंतर्गत चयनित गांवों में होम-स्टे (किसी स्थानीय परिवार के घर में यात्री का रुकना), सांस्कृतिक कार्यक्रमों, जैव-विविधताओं के संरक्षण व सामुदायिक भागीदारीता पर विशेष बल दिया गया है। इससे न केवल रोजगार और आय बढ़ी है, बल्कि गाँवों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ढांचे में भी समग्र विकास दृष्टिगोचर हुआ है।

सतत विकास के दृष्टिकोण से विभिन्न अध्ययनों में स्थानीय समुदायों को पर्यटन से प्राप्त लाभों के समान वितरण, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी की वहनीयता, कचरा प्रबंधन, पारिस्थितिकी पर्यटन के विस्तार और नीति प्राथमिकता पर विशेष बल दिया गया है, इसके अतिरिक्त, नयी नीति बनाने और बहु-हितधारक समन्वय के माध्यम से अधोसंरचनागत, पर्यावरणीय एवं सांस्कृतिक चुनौतियों के सतत समाधान की आवश्यकता भी रेखांकित की गई है।

इस प्रकार, शोध साहित्य, सरकारी रिपोर्ट एवं योजनागत दस्तावेज़ों का विश्लेषण करता है कि, मध्य प्रदेश की पर्यटन नीति, महिला नेतृत्व, सामुदायिक सहभागिता, और ग्रामीण परियोजनाएं, क्षेत्रीय विकास में मील का पत्थर सिद्ध हो रही हैं, लेकिन अधोसंरचना, पर्यावरणीय दबाव, लाभ वितरण की असमानता और सांस्कृतिक संरक्षण की चुनौतियां अभी भी बाकी हैं, जिनके समाधान हेतु बहु-आयामी नीति व स्थानीय भागीदारी अतिआवश्यक है।

3. शोध के उद्देश्य

- मध्य प्रदेश के वंचित समुदायों में पर्यटन के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का अध्ययन।
- पर्यटन के द्वारा कौशल विकास और रोजगार सृजन की संभावनाओं का विश्लेषण।
- सतत विकास के सिद्धांतों के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों का मूल्यांकन।
- वंचित समूहों और स्थानीय आदिवासीयों के पर्यटन से जुड़े अनुभवों और चुनौतियों की पहचान।

4. अध्ययन क्षेत्र और डेटा स्रोत

मध्य प्रदेश के प्रमुख आदिवासी क्षेत्रों जैसे मंडला, बालाघाट, दमोह, शहडोल आदि जिलों का चयन अध्ययन के लिए किया गया है। डेटा- संग्रह के लिए द्वितीयक स्रोत जैसे मध्य प्रदेश पर्यटन निगम की अनुसंधान पत्र, सरकारी सांख्यिकी, रिपोर्टें, और प्राथमिक स्तर पर क्षेत्रीय सर्वेक्षण आदि का उपयोग किया गया है।

5. अध्ययन क्षेत्र (Research Area)

अध्ययन का प्रमुख क्षेत्र है:

- मध्य प्रदेश के वंचित और आदिवासी समुदायों में पर्यटन के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों का गहन अध्ययन।
- सतत विकास के संदर्भ में पर्यटन आधारित रोजगार सृजन, कौशल सशक्तिकरण, एवं सांस्कृतिक संरक्षण की भूमिका।

यह क्षेत्र पर्यटन के द्वारा वंचित वर्ग के योगदान को सतत सामाजिक-आर्थिक विकास की दृष्टि से समझने पर केंद्रित है। साथ ही, इसमें पर्यटन से उत्पन्न पर्यावरणीय संरक्षण के प्रयासों का विश्लेषण भी शामिल होगा।

6. डेटा संग्रह विधि (Method of Data Collection)

इस अध्ययन का मुख्य क्षेत्र है:
"मध्य प्रदेश के वंचित और आदिवासी समुदायों में पर्यटन के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव का अध्ययन, और सतत विकास के संदर्भ में पर्यटन आधारित कौशल सशक्तिकरण, रोजगार सृजन एवं सांस्कृतिक संरक्षण की भूमिका।

"यह क्षेत्र पर्यटन के द्वारा वंचित वर्ग के योगदान को सतत सामाजिक-आर्थिक विकास की दृष्टि से समझने पर केंद्रित है तथा इसमें पर्यटन से उत्पन्न पर्यावरणीय संरक्षण के प्रयासों का विश्लेषण भी शामिल होगा।

इस अध्ययन में द्वितीयक डेटा संग्रह पर आधारित पद्धति अपनाई गई है।

1) **सरकारी रिपोर्टें और दस्तावेज:**
- मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की वार्षिक रिपोर्टें
- सांख्यिकी विभाग और जनगणना रिपोर्टें
- पर्यटन मंत्रालय की योजनाएँ तथा परियोजना दस्तावेज
- मध्य प्रदेश राज्य सरकार के आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास संबंधी प्रकाशित दस्तावेज

2) **अकादमिक और शोध प्रकाशन:**
- पहले से प्रकाशित शोध पत्र, लेख, और समीक्षा ग्रंथ
- शोध संस्थानों और विश्वविद्यालयों की रिपोर्टें
- क्षेत्रीय केस स्टडीज़

3) **सांख्यिकीय डेटा और डेटाबेस:**
- पर्यटक आगमन, विकास के आँकड़े और रोजगार सृजन
- पर्यावरणीय संरक्षण डेटा तथा सतत विकास सूचकांक

4) **विकास एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनो (NGO) द्वारा प्रकाशित जानकारी:** वंचित समुदायों और आदिवासीयों के विकास से जुड़े शोध और प्रोजेक्ट रिपोर्टस

5) **मीडिया रिपोर्ट तथा समाचार स्रोत:**
- पर्यटन के क्षेत्र में हुई मुख्य घटनाओं और पहलों पर नवीनतम समाचार

7. डेटा विश्लेषण की विधि (Data Analysis Method)

1) **सांख्यिकीय विश्लेषण (Statistical Analysis):** पर्यटन से सम्बंधित आर्थिक आंकड़ों, रोजगार और कौशल विकास से जुड़े डेटा का तुलनात्मक और वर्णनात्मक विश्लेषण।
2) **साहित्य समीक्षा (Literature Review):** द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त समसामयिक सजगता और विषयगत दृष्टिकोणों का समेकित विश्लेषण।
3) **तुलनात्मक विश्लेषण (Comparative Analysis):** विभिन्न नीतियों/ परियोजनाओं तथा उनके प्रभावों की तुलना।
4) **सामाजिक – आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण (Socio-Economic Impact Analysis):** पर्यटन विकास की सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावों की प्रणालीगत व्याख्या।
5) **नैतिक एवं पर्यावरणीय आयामों का गहन अध्ययन (Ethical & Environmental Dimensions):** पर्यटन के पर्यावरणीय संरक्षण और नीति-अनुकूलन संबंधी पहलुओं का गहन विश्लेषण।

8. शोध पद्धति: द्वितीयक (सेकेंडरी) डेटा आधारित शोध पद्धति

इस शोध में द्वितीयक डेटा संग्रह पद्धति अपनाई गई है, जिसमें शोधकर्ता ने स्वयं सीधे वास्तविक क्षेत्र में जाकर डेटा एकत्रित करने के बजाय पहले से उपलब्ध, प्रकाशित एवं संग्रहित सूचनाओं और आंकड़ों का उपयोग किया है। इस पद्धति के अंतर्गत प्रमुख स्रोत जैसे की मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के दस्तावेज, सांख्यिकी विभाग की रिपोर्ट, सरकारी रिपोर्ट, , अनुसंधान लेख, अकादमिक जर्नल्स, सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण, मीडिया रिपोर्ट और नीतिगत दस्तावेज सम्मिलित हैं।

शोध पद्धति के तत्व

1) **डेटा स्रोत**
- मध्य प्रदेश पर्यटन निगम और राज्य सरकार की वार्षिक तथा विशेष रिपोर्टें।
- जनगणना और अन्य सरकारी सांख्यिकीय डेटा।

- पूर्व में प्रकाशित शोध पत्र, केस स्टडीज़ और अकादमिक प्रकाशन।
- गैर-सरकारी संगठनों एवं विकास एजेंसियों के दस्तावेज।
- समाचार एवं मीडिया रिपोर्टों से संकलित ताजा जानकारी।

2) डेटा संचयन

- द्वितीयक स्रोतों से प्रासंगिक सूचनाओं का चयन, एकत्रीकरण और तर्कसंगत तरीके से वर्गीकृत किया गया, यह सभी डेटा अध्ययन के उद्देश्य के अनुरूप सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं का सम्पूर्ण चित्र प्रस्तुत करते हैं।

3) डेटा विश्लेषण

- सांख्यिकीय विश्लेषण: आर्थिक, सामाजिक और रोजगार से जुड़े आंकड़ों का तुलनात्मक एवं वर्णनात्मक विश्लेषण।
- साहित्य समीक्षा: द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से संबंधित विषयों पर उपलब्ध तथ्यों और तर्कों का समेकित अध्ययन।
- तुलनात्मक अध्ययन: विभिन्न समय, स्थान और परियोजना स्तर पर पर्यटन के प्रभाव का तुलनात्मक मूल्यांकन।
- नीति विश्लेषण: राज्य सरकार और अन्य निकायों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की प्रभावशीलता का विश्लेषण।
- सांस्कृतिक और पर्यावरणीय आयामों का गहन अध्ययन: पर्यटन से जुड़ी सांस्कृतिक संरक्षण गतिविधियों और पर्यावरणीय प्रबंधन प्रयासों का समालोचनात्मक मूल्यांकन।

4) पद्धति की सीमाएँ और सावधानियाँ

- द्वितीयक डेटा की सटीकता और प्रासंगिकता पर निर्भरता।
- डेटा उपलब्धता में असमानता और अद्यतनीकरण की समस्या।
- स्रोतों के अलग-अलग दृष्टिकोणों से उत्पन्न असंगतियों का समाकलन।

9. निष्कर्ष

पर्यटन के कारण वंचित समुदायों की आय में वृद्धि हुई है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है।कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों और स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हुए हैं,पर्यटन ने स्थानीय सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक कलाओं के संरक्षण को प्रोत्साहित किया है।सतत विकास के दृष्टिकोण से पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में भी पर्यटन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अभी भी कुछ स्थानीय चुनौतियाँ हैं, जैसे की बुनियादी सुविधाओं का अभाव, पर्यावरणीय दबाव, और जनजातीय अधिकारों की सुरक्षा।मध्य प्रदेश में पर्यटन वंचित समुदायों के सतत विकास का एक प्रभावी माध्यम सिद्ध हुआ है, यह न केवल आर्थिक सशक्तिकरण में मदद करता है, अपितु सामाजिक- सांस्कृतिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। स्थानीय हितधारकों, सरकार और पर्यटन प्रबंधन के सामंजस्यपूर्ण प्रयासों से इन समुदायों की जीवन गुणवत्ता और विकास में और वृद्धि संभव है।

सुझाव

- कौशल विकास हेतु कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का व्यापक विस्तार।
- पर्यटन क्षेत्र में वंचित समुदायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लक्षित योजनाओं का क्रियान्वयन।
- पर्यावरणीय संरक्षण को प्रोत्साहित करने हेतु स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन प्रथाओं का संवर्धन।
- पर्यटन-संबंधी बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं का सुदृढ़ विकास।

मध्य प्रदेश पर्यटन निगम की रिपोर्ट, स्थानीय सरकारी सांख्यिकीय योजनाओं, क्षेत्रीय सर्वेक्षणों, साक्षात्कारों से प्राप्त आंकड़ों, संबंधित शोध पत्रों और साहित्य समीक्षाओं पर आधारित यह शोध अध्ययन, मध्य प्रदेश में पर्यटन के माध्यम से स्थानीय वंचित एवं आदिवासी समुदायों के विकास का एक समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें सतत विकास से जुड़े विविध आयामों का समावेश किया गया है, जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रगति के अंत:संबंधों को उजागर करते हैं।

संदर्भ

1. शाह, पी. के., & चौरसिया, पी. के. (2025). मध्य प्रदेश में जनजातीय पर्यटन: संभावनाएं और चुनौतियां. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन एंड रिव्यूज, 6(7), 5446-5453।

2. पानिग्रही, एन. (2023). मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति पर केस स्टडी. द स्कोल्डज इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी एंड अलाइड स्टडीज।
3. बंदु, एस. (2024). भारत में जीआईएस तकनीक के माध्यम से जनजातीय पर्यटन का अध्ययन. क्वेस्ट जर्नल ऑफ रिसर्च इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, 12(7), 95-104।
4. कुमार, पी., & शर्मा, ए. (2023). मध्य प्रदेश में जनजातीय संस्कृति और सतत विकास का सिंहावलोकन. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ नॉवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 8(6)।
5. प्रमोद, के. जे., एट अल. (2017). मध्य प्रदेश के आलीराजपुर जिले के सन्दर्भ में पर्यटन की जनजातीय विकास में भूमिका, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ टूरिज्म, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट।
6. सिंह, एन. पी. (2023) मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में जनजातीय समुदाय की भूमिका (विशेष फोकस: बेतुल जिला), इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फ़ूड एंड न्यूट्रिशनल साइंसेज, 12(1S)।
7. भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय एवं मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड (2024-2025),वार्षिक रिपोर्ट और नीति दस्तावेज।
8. कुरुक्षेत्र पत्रिका (2022) जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन क्षमता. अक्टूबर अंक।
9. दास गुप्ता, डी., एट अल. (2022) सीधी जिले में पर्यटन विकास की संभावनाएं: एक अध्ययन, IJARSCT।
10. मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, वार्षिक रिपोर्ट (2023-2025)।
11. त्रिपाठी, आर. एन. (2019), जनजातीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक पर्यटन. श्रृंखला: एक शोधपरक वैचारिक पत्रिका, 6(5)।
12. भट्टाचार्य, एस., & कुमार, आर. (2024), सतत जनजातीय पर्यटन: बस्तर क्षेत्र की केस स्टडी. जर्नल ऑफ एनवायरनमेंट एंड टूरिज्म, 9(2)।
13. जोशी, ए. के. (2022), मध्य प्रदेश के जनजातीय पर्यटन में चुनौतियां एवं अवसर. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रूरल मैनेजमेंट।
14. शर्मा, वी. (2023). मध्य प्रदेश के जनजातीय समुदायों पर पारिस्थितिक पर्यटन का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव. जर्नल ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म स्टडीज।
15. मिश्रा, एस., & वर्मा, पी. (2024). मध्य प्रदेश में जनजातीय पर्यटन में महिलाओं की भूमिका. इंडियन जर्नल ऑफ जेंडर स्टडीज।
16. रौतेला, पी. (2023). पर्यटन विकास और स्वदेशी समुदाय: सपरुआ टाइगर रिज़र्व का मामला. वाइल्डलाइफ़ एंड सोसाइटी जर्नल।
17. सिंह, एम., & गुप्ता, एच. (2022). मध्य भारत में जनजातीय पर्यटन विकास में सामुदायिक सहभागिता. एशियन जर्नल ऑफ टूरिज्म रिसर्च।
18. यादव, के. (2023). मध्य प्रदेश में डिजिटल मीडिया का जनजातीय पर्यटन प्रचार पर प्रभाव. जर्नल ऑफ कल्चरल हेरिटेज एंड कम्युनिकेशन।
19. वर्मा, डी., & शुक्ला, एस. (2024). मध्य प्रदेश में जनजातीय पर्यटन विकास पर नीतिगत पक्ष. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पब्लिक पॉलिसी।
20. चौधरी, आर. (2023). मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय स्थिरता और पर्यटन. जर्नल ऑफ एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट।